

Regarding problem of drinking water and irrigation in Eastern Rajasthan

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : महोदया, मैं राजस्थान के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी से संबंधित है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिले, वर्तमान में 21 जिलों में पीने तथा सिंचाई के जल की समस्या के निराकरण के संबंध में, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राजस्थान में देश का 10.41 प्रतिशत भू-भाग आता है। कृषि क्षेत्र के दृष्टिकोण से देश का 13.88 प्रतिशत कृषि क्षेत्र राजस्थान के पास है। देश का 11 प्रतिशत पशु धन राजस्थान में है और आबादी के 5.67 प्रतिशत लोग राजस्थान में निवास करते हैं। जल संसाधनों के दृष्टिकोण से देश में राजस्थान की स्थिति अत्यन्त विषम एवं चिन्ताजनक है। राजस्थान के हिस्से में देश में उपलब्ध भूजल का मात्र 1.6 प्रतिशत एवं सतही जल का 1.16 प्रतिशत आता है। वर्ष 2022 में किए गए एक सर्वे के अनुसार राजस्थान में कुल 302 ब्लॉक्स में से 264 ब्लॉक्स की स्थिति पानी के अति दोहन के चलते अत्यन्त गम्भीर हो गई है। बचे हुए 38 ब्लॉक्स भी तेजी से डार्क जोन में परिवर्तित होते जा रहे हैं।

महोदया, इन परिस्थितियों को देखते हुए पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों, वर्तमान में 21 जिलों के लिए ईआरसीपी योजना के लिए वर्ष 2016-17 की डीपीआर तत्कालीन राजस्थान सरकार ने 50 प्रतिशत जल निर्भरता पर बनाई थी। इससे इन 13 जिलों को 3,921 एमसीएम पानी मिलना था। इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर, अपने नये एमओयू में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान व केन्द्र सरकार के मध्य पीकेसी रिवर लिंक के नाम से एक नया एमओयू कर लिया गया। जैसी मुझे जानकारी मिली है कि यह एमओयू 75 प्रतिशत जल निर्भरता पर किया गया है। इससे राजस्थान को मात्र 1,775 एमसीएम पानी ही मिलेगा, जो बहुत कम है। राजस्थान की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित पीकेसी एमओयू की समीक्षा करते हुए 50 प्रतिशत जल निर्भरता पर ही योजना लागू की जाए। मैं आपसे यह मांग करता हूँ।

सभापति महोदया, मेरा एक निवेदन और है। आज ट्राइबल डे है। सबको ट्राइबल डे मुबारक हो। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान में इस आदिवासी दिवस की छुट्टी सरकार द्वारा घोषित है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि ट्राइबल डे की छुट्टी पूरे देश में भी घोषित की जाए। ? (व्यवधान)